से विचार-विमर्श करके सरकारी योजनाओं को उस ग्रामीण भोली-भाली जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे?

†**محترمہ کہکشاں پروین:** میں مانئے منتری جی سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سرکار کی جتنی لابھکاری یوجنائیں ہیں، ان یوجناؤں کا لابھ عام جنوں تک پہنچے، اس کے لئے کیا وہ سارے منترالیوں سے وچار ومرش کرکے سرکاری یوجناؤں کو اس گرامین بھولی بھالی جنتا تک پہنچانے کا کام کریں گے؟

श्री धोत्रे संजय शामराव: सर, जो पोस्टमैन या डाकिया है, हम उसको सबसे विश्वसनीय समझते हैं और वह हमारे परिवार का ही एक हिस्सा होता है। उसके लिए बहन जी ने बहुत अच्छे शब्द कहे, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सारी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बहुत अच्छा सुझाव दिया है। निश्चित ही हम इसके लिए प्रयासरत हैं और सभी के साथ बातचीत करके निश्चित ही हम इसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाएँगे।

श्री उपसभापति: प्रश्न संख्या 49.

देश में शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किया जाना

*49. **श्री नारायण राणे**: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु कौन-सा तंत्र विद्यमान है;

(ख) यह तंत्र किस प्रकार से काम कर रहा है;

(ग) देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें सुधार करने में यह तंत्र किस हद तक सफल रहा है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) इस देश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करने वाले तंत्र का विवरण निम्नलिखित है:

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता

(i) उच्च शिक्षा की गुणवत्ता हेतु संस्था के अपनी प्रक्रियाओं और कार्य प्रणाली के आधार पर 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्' (एन.ए.ए.सी.) NAAC द्वारा आकलन

†Transliteration in Urdu script.

(ii) उच्च शिक्षण संस्थाओं के पारस्परिक रैंक के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) द्वारा वार्षिक रैंकिंग की प्रणाली

(iii) तकनीकी शिक्षा में गुणता के आकलन हेतु राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड (NBA)

विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता

(i) विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता हेतु वर्ष 2017 में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)

(ii) प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) के तहत राज्यों एवं कें द्रीय शाषित क्षेत्रों के विद्यालयों का मूल्यांकन

(iii) नीति आयोग द्वारा वर्ष 2019 में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (School Education Quality Index-SEQI), की पहल।

यह तंत्र सफलतापूर्वक काम कर रहा है। गुणता में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके तहत उच्च शिक्षा में वर्ष 2019 तक प्रमाणित कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 606 एवम् प्रमाणित कॉलेज की संख्या 12709 है। वर्ष 2019 में NIRF में भाग लिये गये संस्थानों की संख्या 4867 है। वर्ष 2019 में NBA में भाग लिये गये संस्थानों की संख्या 4867 है।

विद्यालय शिक्षा में विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता हेतु वर्ष 2017 में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) सभी 36 राज्यों एवम् केन्द्रशासित क्षेत्रों के विद्यालयों में किया गया। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) के तहत राज्यों एव केंद्र शासित क्षेत्रों के विद्यालयों में वर्ष 2019 में स्कूली शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन किया गया। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2019 में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (School Education Quality Index-SEQI), विद्यालय शिक्षा के गुणता के आकलन हेतु एक नई शुरुआत की गयी।

Assessing quality of education in the country

†*49. SHRI NARAYAN RANE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the mechanism in place to assess the quality of education in the country;

(b) the manner in which this mechanism is working;

(c) the extent to which this mechanism has been successful in maintaining and improving the quality of education in the country; and

(d) the response of Government thereto?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) to (d) Following is the description of the mechanisms that work to ensure the quality of education in this country:

Quality of higher education

(i) Assessment by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) based on the institution's own processes and procedures for the quality of higher education.

(ii) System of annual ranking by National Institutional Ranking Framework (NIRF) for determining inter-se rank of higher educational institutions.

(iii) National Board of Certification (NBA) for assessment of quality in technical education.

Quality of school education

(i) National Achievement Survey (NAS) in the year 2017 for the quality of school education.

(ii) Evaluation of schools in states and centrally governed areas under Performance Grading Index (PGI).

(iii) Initiative of School Education Quality Index-SEQI, in the year 2019 by NITI Aayog.

This system is working successfully. Improvement in quality is a continuous process. Under it, in the area of Higher Education, till the year 2019, a total of 606 Universities and 12709 colleges have been NAAC accredited. In 2019, the number of institutions which participated in NIRF is 4867. In 2019, the number of institutions which participated in NBA is 4867.

In the area of school education, the National Achievement Survey (NAS) was held in the year 2017 for the quality of school education. It was conducted in schools in all 36 States and Union Territories. Under the Performance Grading Index (PGI), the schooling system was also evaluated in the year 2019 in schools in the States and Union Territories. In the year 2019, the School Education Quality Index-SEQI, a new initiative has also been established by NITI Aayog to assess the quality of school education.

श्री नारायण राणे: उपसभापति महोदय, 'देश में शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन' रिपोर्ट आ चुकी है। मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि क्या सरकार की इस तंत्र में बदलाव लाने की कोई सोच है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, उच्च शिक्षा में इसका मूल्यांकन करने की दृष्टि से हम लोग तीन स्तर पर आकलन करते हैं। NAAC एक संस्था है, जिसके माध्यम से हम आकलन करते हैं, दूसरा हम NIRF के तहत करते हैं और तीसरा NBA के तहत करते हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए तीनों का आधार होता है। ऐसे ही स्कूली शिक्षा में भी हम लोग आकलन करते हैं। हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) कराते हैं, PGI कराते हैं और नीति आयोग भी आकलन कराता है। माननीय सदस्य ने जिस बात को उठाया है कि ये जो सर्वेक्षण होते हैं, उनका क्या रिजल्ट है, तो मुझे यह बताते हुए खुशी है कि NAAC में काफी तेजी से हमारे विश्वविद्यालय आ रहे हैं और उन मानकों को पूरा कर रहे हैं। भारत में जनवरी, 2020 तक कुल 1,028 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से अभी 606 विश्वविद्यालय NAAC के अन्दर आ गए हैं, जबकि 39,931 कॉलेज हैं, जिनमें से 12,709 कॉलेज हमारे NAAC के स्तर पर आ चुके हैं। ऐसे ही NIRF में भी 4,867 कॉलेज ने भाग लिया, जबकि प्रबंधन और तकनीकी के क्षेत्र में NBA जो आकलन करता है, उसमें भी हमारे 4,867 संस्थान ने भाग लिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. दूसरा सप्लीमेंटरी।

श्री नारायण राणे: महोदय, भविष्य में अपनी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, हम लोग इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। उच्च शिक्षा का स्तर बढ़े, उसमें हम अध्यापकों के लिए ARPIT कार्यक्रम कर रहे हैं। नीचे स्कूली शिक्षा के लिए हम NISHTHA कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें 42 लाख अध्यापकों का प्रशिक्षण संभवत: दुनिया का पहला ऐसा बड़ा कार्यक्रम है। फिर हमारा LEAP कार्यक्रम है, जिसमें हमारे VCs हैं, Directors हैं, Principals हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके, उनके लिए हम LEAP के तहत कार्यक्रम करते हैं। अनुसंधान की दृष्टि से SPARC है, STRIDE है, IMPRESS है, IMPRINT है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे शोध की दिशा में हमारा GIAN है, GIAN plus है, History in India है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं, जबकि UGC के स्तर पर भी Paramarsh है, Deeksharambh है, Margdarshak है, Smart India Hackathon है। इसी तरह से नीचे स्कूली शिक्षा में DHRUV है, Atal Tinkering Lab है। श्रीमन्, यदि आप देखेंगे, तो हमने IoE के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व रैंकिंग के लिए उत्कृष्ट श्रेणी के 20 ऐसे संस्थानों को भी अभी अनुमति दी है। लगातार इन शोध ...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, kindly briefly reply दें। बहुत questions करने हैं।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': जी। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो वे कह रहे हैं, उस दिशा में सरकार गम्भीर है और बहुत तेजी से प्रयास कर रही है।

श्री उपसभापति: श्रीमती विप्लव ठाकुर।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन्होंने higher education, universities या बाकी सब चीज़ों के बारे में बात कही है, लेकिन हमारे जो basic primary school हैं, जब तक हम वहां की शिक्षा में सुधार नहीं करेंगे, तब तक कोई बड़ा सुधार संभव नहीं होगा। स्कूलों के लिए आपने जो नॉर्म्स बना रखे हैं कि इतने स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर होगा, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? प्राइमरी स्कूलों में ही हमारे बच्चों की foundation बनती है। क्या आप वहां पर टीचर्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं और क्या आप वहां की एजुकेशन में कोई सुधार ला रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': महोदय, स्कूली शिक्षा के उन्नयन की दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं न केवल कार्यक्रम बनाए गए है, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया गया है और न केवल गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है, बल्कि उनका रिज़ल्ट कैसे निकलेगा, इस दिशा में भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और विचार ही नहीं कर रही है, बल्कि काम भी कर रही है। इसका एक उदाहरण 'निष्ठा' है।

श्रीमन्, स्कूलों में 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम' चलाया गया है। शायद यह दुनिया का पहला ऐसा देश होगा, जो स्कूली शिक्षा से ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिखाएगा। समग्र शिक्षा के तहत अंतिम छोर तक के बच्चे को शिक्षा कैसे मिले, उस दिशा में हमारा पूरा ध्यान है।

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जो जवाब दिया है, उसके अनुसार क्वालिटी की जांच के लिए इन्होंने कई तरह की एजेंसीज़ बना दी हैं, लेकिन सच बात यह है कि सारी व्यवस्था की क्वालिटी की जांच के लिए जब तक आप ठीक टीचर्स नहीं रखेंगे, तब तक व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल के टीचर या हेडमास्टर से जब सवाल पूछा जाता है, तो वे प्रधान मंत्री का नाम तक नहीं जानते हैं। हमारे पास M.Sc. का एक लड़का आया और कहने लगा कि सर, आप हमारे लिए कॉलेज में सिफारिश कर दीजिए, लैक्चरर का इंटरव्यू है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा विषय क्या है? वह कहने लगा Physics है। मैंने पूछा कि Newton's third law of motion क्या है? He didn't know. जो M.Sc. (Physics) कर चुका है और Physics के lecturer के लिए इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है, वह यह नहीं जानता है कि Newton's Third Law of Motion क्या है? इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसको मॉनिटर कीजिए और दोबारा विचार कीजिए। इसे आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं कि चौथी श्रेणी का लड़का उतना जानता है या नहीं जानता, जितना उसी क्लास के एक एवरेज लड़के को जानना चाहिए। M.Sc. या M.A. का लड़का उतना जानता है कि नहीं जानता, जितना उसे जानना चाहिए? टीचर्स की जांच के लिए आपने कौन सी एजेंसी नियुक्त की है, जो यह देखे कि वे सही पढ़ा सकते हैं या नहीं?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': आदरणीय राम गोपाल जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: वे एक अनुभवी शिक्षक भी हैं।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': जी हां। उनको यह जान कर बहुत खुशी होगी कि इसके लिए 'अर्पित' कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उच्च शिक्षा के अध्यापकों एवं प्राध्यापकों को हर हालत में प्रति वर्ष 'अर्पित' से होकर गुजरना पड़ेगा तभी यह संभव होगा कि जिस बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं, वह नित्य नये अनुसंधान और पाठ्यक्रम से जुड़कर कर चुनौतियों का मुकाबला कर सके। जो अध्यापक इसे उत्तीर्ण नहीं करेगा, उसकी प्रोन्नत्ति को रोका जाएगा। स्कूली शिक्षा में 'निष्ठा' के माध्यम से अध्यापक को ही तैयार करना होगा, ऐसे अध्यापक जो पूरी ताकत और अद्यतन जानकारियों के साथ बच्चों को सिखा सकें, पढ़ा सकें। श्रीमन्, वैसे भी अब वह युग चला गया है, जब लोग बिना परीक्षा के ही पास हो जाते थे और दसवीं में जाकर एक अजीब सी स्थिति में आ जाते थे। अब स्कूली शिक्षा में परीक्षा होगी, गुणवत्ता के स्तर की जांच होगी और बच्चा हर स्तर पर परखा जाएगा।

डा. अशोक बाजपेयी: मान्यवर, शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में और आज निरंतर जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, उसके संबंध में मेरा एक प्रश्न है। आज निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों के व्यवसायीकरण के कारण शिक्षित नवयुवकों में सेवा भावना और राष्ट्रीयता की भावना कम हो रही है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: बाजपेयी जी, आप सवाल पूछिए।

डा. अशोक बाजपेयी: महोदय, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। इन संस्थानों में पढ़ कर निकले स्नातक नवयुवक धनोपार्जन को ही अपना लक्ष्य बना रहे हैं। क्या सरकार इसका संज्ञान लेकर, इसकी कोई चिंता करेगी? पहले शिक्षा में सेवा भावना और राष्ट्रीयता की भावना होती थी। मान्यवर, आज लोग M.S. और M.D. के लिए एक-एक करोड़, दो-दो करोड़ रुपये देकर प्रवेश पाते हैं।...(व्यवधान)..

श्री उपसभापति: आपका सवाल पूरा हो गया है। माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, हम जो नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, वह मूल्यपरक होगी, भारतीय शिक्षा पर आधारित होगी और आप जिन मूल्यों की बात कर रहे हैं, उन पर आधारित होगी। जहां तक निजी संस्थानों की स्वायत्तता का प्रश्न है, हमेशा से ही यह बात रही है कि जो शीर्ष संस्थाएं हैं, उनके पास स्वायत्तता रहनी चाहिए। उन पर सरकारी नियंत्रण कम रहेगा, तो वे अपने स्तर पर उठेंगे। श्रीमन्, यह तो प्रतिस्पर्धा का जमाना है। जो अच्छा पढ़ायेगा, शीर्ष तकनीकी से लेकर सब अच्छा देगा, छात्र वहाँ जायेंगे। ...**(व्यवधान)**... लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल प्राइवेट क्षेत्र में, बल्कि सरकारी क्षेत्र में भी, चाहे वह IIT हो, NIT हो या IIIT हो, हम लोग सरकारी क्षेत्र में भी स्तरीय शिक्षा दे रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Question No.50. This question is related to Karnataka.